Drishti IAS

करेंट अफेयर्स झारखंड

मार्च (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड **3**

- केंद्र सरकार ने रद्द किया धालभूमगढ़ में बनने वाले एयरपोर्ट का प्रस्ताव 3
- एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में देश का पहला वातानुकूलित कंडेनसर चालू किया 3
- झारखंड बजट 2023-24 4
- 'मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप' योजना 5
- सोलर सिटी बनने की ओर जमशेदपुर 6
- शेखर मल्लिक को भारतीय भाषा परिषद देगी युवा पुरस्कार 6
- BIT मेसरा में शुरू होगी 'साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव' 7
- सैफ अंडर-17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिये भारतीय टीम में झारखंड की सात महिला फुटबॉलर शामिल 8
- मुख्यमंत्री ने 'झारनियोजन पोर्टल' का किया उद्घाटन 9
- पलामू में पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन का गठन 10
- हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट ज़ोन हॉकी चैंपियनशिप 2023 10
- राँची में उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन 11
- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने झारखंड को दिया 11,400 करोड़ रुपए की 21 सड़क परियोजनाओं का तोहफा 12
- ईस्ट ज़ोन जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 13
- झारखंड में जल्द बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 फोरलेन कॉरिडोर 14
- झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में 44 फैसलों को दी मंजूरी 15
- झारखंड के खिलाड़ियों को विश्व चैंपियनशिप में भागीदारी करने पर भी मिलेगा अब कैश अवॉर्ड 16
- नाबार्ड ने झारखंड के लिये बनाई 43 हज़ार करोड़ की क्रेडिट योजना 16

नोट :

झारखंड

केंद्र सरकार ने रद्द किया धालभूमगढ़ में बनने वाले एयरपोर्ट का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

27 फरवरी, 2023 को केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पर्यावरण संरक्षण एवं एलीफेंट कोरिडोर होने का कारण दर्शाते हुए झारखंड के धालभूमगढ़ (पूर्वी सिंहभूम) में एयरपोर्ट निर्माण के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत जमशेदपुर में टाटा स्टील के स्वामित्व वाले सोनारी हवाई अड्डा से उड़ानों का संचालन शुरू हो चुका है तथा धालभूमगढ़ में द्वितीय विश्वयुद्ध का परित्यक्त हवाई अड्डा है, जो वर्तमान में जर्जर हालत में है तथा संचालन के लिये उपयुक्त नहीं है।
- ज्ञातव्य है कि धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड को झारखंड में हवाई अड्डे के विकास के लिये संयुक्त उद्यम कंपनी बनाया गया था। इसके लिये राज्य सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भार मुक्त भूमि उपलब्ध करानी थी।
- इस संबंध में पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने पाया कि प्रस्तावित स्थल जंगलों में पड़ता है तथा बड़ी संख्या में हाथियों का निवास स्थान है तथा यह स्थान हाथी गलियारे के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावित स्थल हवाई अड्डे के विकास के लिये उपयुक्त नहीं है।
- राज्य सरकार द्वारा एएआई को कोई ज़मीन नहीं सौंपी गई तथा साथ ही वन मंजूरी भी प्राप्त नहीं हुई। इसके कारण प्राधिकरण ने धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया है।
- विदित है कि धालभूमगढ़ में द्वितीय विश्वयुद्ध काल के एयरपोर्ट को चालू करने के लिये रघुवर दास सरकार ने पहल की थी। एयरपोर्ट का भूमि पूजन 24 जनवरी, 2019 को किया गया था।
- केंद्र सरकार द्वारा एयरपोर्ट के लिये 100 करोड़ की राशि भेजने के बाद भी 4 साल में एक ईंट तक नहीं जुड़ी है। राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति नहीं मिलने के कारण काम अधर में अटका हुआ था।

एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में देश का पहला वातानुकूलित कंडेनसर चालू किया

चर्चा में क्यों ?

1 मार्च, 2023 को देश की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादक कंपनी, एनटीपीसी ने रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल के माध्यम से जल संरक्षण के लिये अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए, झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में भारत का पहला वातानुकूलित कंडेनसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया।

प्रमुख बिंदु

- एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा (3'660 मेगावाट) में 660 मेगावाट की पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है।
- इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) के साथ की गई है, जिसमें पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडेनसर (डब्ल्यूसीसी) की तुलना में लगभग 1/3 वाटर फुटप्रिंट है। इसके माध्यम से एक वर्ष में लगभग 5 एमसीएम पानी की बचत होगी और इस प्रकार से इस क्षेत्र में वार्षिक रूप से लगभग 15 लाख लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

नोट :

- एनटीपीसी द्वारा पहले ही अपने संयंत्रों में जल का ठोस प्रबंधन करने के लिये अनेक उपाय किये गए हैं। एनटीपीसी, विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधि के साथ-साथ जल संरक्षण और प्रबंधन करने के लिये 3 आर (रिड्यूस, रियूज, रीसायकल) को बढ़ावा देगा। एनटीपीसी लिमिटेड प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट्स सीईओ वाटर मैंडेट का एक हस्ताक्षरकर्त्ता भी है।
- एनटीपीसी जल नीति को लागू करते हुए जल संवहनीयता के मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिये प्रतिबद्ध है, जो जल प्रबंधन रणनीतियों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं और अनुसंधान पहलों की स्थापना के लिये एक दिशासूचक के रूप में काम करेगा।
- उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र में 660 मेगावाट की 3 इकाइयाँ होंगी जिसकी कुल क्षमता 1,980 मेगावाट होगी। यह संयंत्र सबसे कुशल सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित है और एक पिट हेड संयंत्र (कोयला खदान से 10 किमी.) होने के कारण झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों को सस्ते दामों पर विद्युत की आपूर्ति करेगा।
- एनटीपीसी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में हमेशा सबसे आगे रहा है और अपने विद्युत क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने का बीड़ा उठाया है। एनटीपीसी वर्तमान में कोयला, गैस, हाइड्रो, सौर और पवन संयंत्रों के माध्यम से देश में विद्युत की 24 प्रतिशत मांग को पूरा करता है।

झारखंड बजट 2023-24

चर्चा में क्यों ?

3 मार्च, 2023 को झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार के बजट में ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि किसानों को सिंचाई का लाभ देने के लिये और जल संरक्षण के दृष्टिकोण से 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने एवं डीप बोरिंग इत्यादि योजना को लेकर 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा आधारित माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में काफी किफायती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी।

नोट :

- वर्ष 2023- 24 में FPOs के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
- झारखंड बजट 2023-24 के अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु -:
  - वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने के लिये 300 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नये डेयरी प्लांट एवं रांची में मिल्क पाउडर प्लांट व मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिये 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।
  - सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिये मनरेगा तथा राज्य योजना का अभिसरण करते हुए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा।
  - आम लोगों को पंचायत स्तर पर सभी सुविधाएँ एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू की जा रही है। सभी पंचायत सचिवालयों में पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण-पत्र, ऑनलाइन सुविधाएँ, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से संबंधित सुविधाएँ, निर्धारित दिवस पर हल्का से संबंधित कार्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  - विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिये प्रोत्साहन राशि, महिलाओं में स्वच्छता के प्रसार को लेकर नि:शुल्क सेनेटरी नैपकीन का वितरण, प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने एवं प्रसव उपरांत मातृत्व केयर किट वितरण करने के उद्देश्य से 'महिला एवं किशोरी कल्याण योजना' शुरू करने का प्रस्ताव है।
  - आंगनबाड़ी केंद्र में आनेवाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा के लिये 'आंगनबाड़ी चलो अभियान' योजना शुरू की जायेगी। इस योजना के तहत बच्चों को पोशाक एवं वर्क-बुक तथा सभी केंद्रों में फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराए जाने के लिये वर्ष 2023-24 में 190 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
  - वर्ष 2023-24 में राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉपआउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
  - नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा।
  - पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। रांची में पीपीपी मोड पर Alcohol De addiction Centre खोला जाएगा।
  - वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए दो लाख युवाओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य है।
  - वर्ष 2023-24 में पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से चले, इस हेतु छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना का प्रस्ताव है।
  - मानकी-मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, डकुआ आदि की न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य भूमिकाओं के महत्त्व को देखते हुए उन्हें वर्ष 2023-24 में दोपहिया वाहन सुलभ कराने का प्रस्ताव है।
  - वर्ष 2023-24 में इन पथ परियोजनाओं को शुरू किया जाना प्रस्तावित है- 1) साहेबगंज-बरहेट - जामताड़ा - दुमका- गोविंदपुर ए.डी.बी. पथ का फोरलेन में उन्नयन, 2) कोडरमा-जमुआ - गिरिडीह टुंडी - गोविंदपुर (SH-13) पथ का फोरलेन में उन्नयन, 3) सतसंग- भिरखीबाद पथ का फोरलेन में उन्नयन, आगामी वित्तीय वर्षों में सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बाज़ार हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य/उच्च विद्यालय, पोस्ट ऑफिस/बैंकों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव है।
  - वर्ष 2023-24 में दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।
  - अमृत 0 योजना अंतर्गत रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना एवं सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना तथा 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य करने का प्रस्ताव है।
  - वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा RTI Portal विकसित किया जाएगा।

'मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप' योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमारी पासी ने बताया कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को 'मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति'योजना का लाभ दिया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने बताया कि 'मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति' योजना के लिये राज्य के 1,47,928 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। इन्हें मार्च में ही छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- योजना के तहत पहली से चौथी कक्षा तक 500 रुपए, पाँचवीं और 6वीं में पढ़ने वालों को 1 हज़ार, कक्षा 7-10 तक के छात्र-छात्राओं को 1500 और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को 2300 रुपए मिलेंगे।
- किरण कुमारी पासी ने बताया कि पहली से 12वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के वैसे छात्र-छात्रा, जिन्हें अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन ऐप के माध्यम से छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिये पीएफएमएस- डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

सोलर सिटी बनने की ओर जमशेदपुर

चर्चा में क्यों ?

10 मार्च, 2023 को झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (जेरेडा) के अधिकारियों ने बताया कि जमशेदपुर शहर सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। अभी वहाँ 37 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट प्रस्तावित है, जिसमें 2.2 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट सोनारी एयरपोर्ट में चालू हो चुका है।

प्रमुख बिंदु

- जेरेडा के अधिकारियों ने बताया कि जमशेदपुर शहर के अलावा अन्य जगहों पर टाटा स्टील और टाटा पावर द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है।
- विदित है कि टाटा स्टील स्थित जलाशयों में 9.8 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है।
- टाटा स्टील परिसर में 9.8 मेगावाट का प्लांट, डोमजोरी में 15 मेगावाट का सोलर प्लांट टाटा पावर द्वारा, टाटा मोटर्स में 3 मेगावाट का रूपटॉप प्लांट, टाटा स्टील में ही 5 मेगावाट रूफटॉप प्लांट, टाटा ब्लूस्कोप में 1.2 मेगावाट का रूफटॉप प्लांट, एयरपोर्ट में 2.2 मेगावाट का प्लांट लगाया जा रहा है।
- राज्य के पूर्वी सिंहभूम ज़िले में 250 मेगावाट बिजली की खपत है। 37 मेगावाट के सौर ऊर्जा के उत्पादन से टाटा स्टील अपनी कॉलोनी में बिजली दे सकता है। इससे काफी हद तक पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम होगी।
- जेरेडा द्वारा वहाँ इसकी संभावना देखी जा रही है कि कहाँ-कहाँ सौर ऊर्जा का प्लांट लग सकता है, चाहे वह रुफटॉप के रूप में हो या फ्लोटिंग प्लांट हो।

शेखर मल्लिक को भारतीय भाषा परिषद देगी युवा पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

13 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता का प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार झारखंड के युवा कथाकार शेखर मल्लिक को दिया जाएगा। इस संबंध में कथाकार शेखर मल्लिक को परिषद ने ईमेल के जरिये सूचना दी है।

प्रमुख बिंदु

- शेखर मल्लिक ने प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार दिये जाने की घोषणा के बाद बताया कि वर्ष 2020 में ही उन्हें यह पुरस्कार दिये जाने का निर्णय हो चुका था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उस वक्त इसकी घोषणा नहीं हो सकी।
- ज्ञातव्य है कि शेखर मल्लिक झारखंड के पूर्वी सिंहभूम ज़िले के घाटशिला के रहने वाले हैं।
- शेखर मल्लिक ने बताया कि भारतीय भाषा परिषद का यह पुरस्कार हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के युवा साहित्यकारों को साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिये दिया जाता है। उनका चयन हिन्दी भाषा के लिये किया गया है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि भारतीय भाषा परिषद का यह पुरस्कार आठ अप्रैल को शेखर मल्लिक को कोलकाता में दिया जाएगा। इस पुरस्कार में लेखक को 41 हज़ार रुपए की राशि, एक स्मृति चिह्न, अभिनंदन पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा।
- झारखंड प्रगतिशील लेखक संघ के उप महासचिव शेखर मल्लिक समकालीन चर्चित युवा लेखक हैं, जिनकी पहली कहानी को प्रतिष्ठित पत्रिका हंस में प्रथम प्रेमचंद कहानी पुरस्कार 2004 हेतु नामित किया गया था।
- उनके तीन कहानी संग्रह स्वीकार और अन्य कहानियाँ, कस्बाई औरतों के किस्से और आधी रात का किस्सागो तथा एक उपन्यास कालचिती प्रकाशित हैं। शेखर मल्लिक IPTA से जुड़े संस्कृतिकर्मी भी हैं।
- शेखर मल्लिक ने बताया कि उनके दो उपन्यास अभी प्रकाशित होने वाले हैं। उनकी कथा रचनाओं के नाट्य रूपांतरण, अन्य भाषाओं में अनुवाद व उन पर शोध कार्य भी हुए हैं।
- इनकी रचनाएँ देश के प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें हंस, उद्घोष, अन्यथा, परिकथा, पाखी, वागर्थ और प्रगतिशील वसुधा शामिल हैं।

BIT मेसरा में शुरू होगी 'साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव'

चर्चा में क्यों ?

15 मार्च, 2023 को झारखंड के राँची के बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) मेसरा के रजिस्ट्रार डॉ. संदीप दत्ता ने लालपुर एक्सटेंशन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इंटरनेट और मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल से साइबर क्राइम से निजात पाने के उद्देश्य से बीआईटी मेसरा में 'साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव'की शुरुआत की जाएगी। आईआईटी कानुपर का सीथ्रीआई हब इसमें सहयोग करेगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि मोबाइल खोने या चोरी होने पर लोगों के डाटा नष्ट हो जाते हैं. खोये डाटा को वापस कैसे लाया जाए, इस पर शोध की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये बीआईटी मेसरा में 'साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव'की शुरुआत की जाएगी।
- आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सह प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीथ्रीआई हब पद्मश्री डॉ. मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस करार के तहत संस्थान में साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के बाद साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार की जाएगी, ताकि आने वाले समय में डाटा सिक्योरिटी, डाटा रिकवरी, डाटा मॉनिटरिंग के साथ साइबर सिक्योरिटी को मज़बूत किया जा सके।
- बीआईटी मेसरा के रजिस्ट्रार डॉ. संदीप दत्ता ने बताया कि इस पहल में भारत सरकार के साइबर सेल एडवाइजर सह सुत्रा मॉडल के जनक पद्मश्री डॉ. मनिंद्र अग्रवाल सहयोग करेंगे। आईआईटी कानपुर के सीथ्रीआई हब के साथ करार किया जाएगा।

नोट :

- डॉ. मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस करार के तहत संस्थान में साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के बाद साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के अंतर्गत संस्था के सभी कंप्यूटर और राउटर की लगातार मॉनिटरिंग हो, इसके लिये इन्वेंट्री तैयार की जाएगी।
- इसके अलावा संस्था के इंजीनियर्स का साइबर हमले से कैसे बचाव किया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिये 'हनी पॉट'जैसी आधुनिक तकनीक विकसित की जाएगी।
- 'हनी पॉट' के तहत साइबर हमले के मूल सोर्स को फेक सर्वर में उलझाने की पहल की जाएगी। साथ ही साइबर सुरक्षा को लेकर विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के बीच लगातार जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे।
- डॉ. मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि देश में टेक्निकल इनोवेशन हब के तहत 25 संस्थानों को अलग-अलग जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। सीथ्रीआई हब इसमें साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इसके लिये बीआइटी के इंजीनियर्स के साथ सीथ्रीआई हब से जुड़े तीन स्टार्टअप टीम मिलकर काम करेगी।
- विदित है कि बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) राँची की स्थापना 1955 में इंडस्ट्रियलिस्ट बी. एम. बिड़ला ने की थी। झारखंड की राजधानी राँची से 16 किलोमीटर दूर 780 एकड़ में फैले बीआईटी मेसरा को यूजीसी से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। इस इंस्टीट्यूट को NAAC (नेशनल असेस्मेंट एंड एक्रडिटेशन काउंसिल) और NBA (नेशनल बोर्ड ऑफ एसोसिएशन) से मान्यता मिली हुई है। इस इंस्टीट्यूट का मुख्य कैंपस मेसरा में है जबकि इलाहाबाद, जयपुर, कोलकाता, नोएडा, पटना, देवघर, लालपुर, मस्कट (ओमान) और दुबई में भी इसके कैंपस हैं।

सैफ अंडर-17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिये भारतीय टीम में झारखंड की सात महिला फुटबॉलर शामिल

चर्चा में क्यो ?

16 मार्च, 2023 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) ने 18 से 29 मार्च तक होनेवाली सैफ अंडर-17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिये 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की, जिसमें झारखंड की सात फुटबॉलर शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय टीम में शामिल झारखंड की सात फुटबॉलर में से चार फुटबॉलर जेएसएसपीएस राँची की प्रशिक्षु हैं, जबकि तीन फुटबॉलर आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, गुमला से हैं।

नोट :

- टीम में झारखंड की जिन सात खिलाड़ियों का चयन किया गया है, उनमें विकसित बाड़ा (डिफेंडर), निशिमा कुमारी (डिफेंडर), बबिता कुमारी (फॉरवर्ड,), अनिषा उरांव (गोलकीपर), शाउलिना डांग (मिडफील्डर), शिवानी टोप्पो (फॉरवर्ड) और ललिता बोयपाई (मिडफील्डर) शामिल हैं।
- विदित है कि टीम चयन के लिये इंदौर में 21-22 फरवरी को ट्रायल का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से 35 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।

मुख्यमंत्री ने 'झारनियोजन पोर्टल' का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

17 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में 'झारनियोजन पोर्टल'का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए इस पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोज़गार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास करेगी।
- पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि नियोजन पोर्टल से निजी क्षेत्र में नियुक्ति की मॉनीटरिंग हो सकेगी। इसकी योजना पहले से लागू है पर वेब पोर्टल की कमी थी। अब यह बेहतर तरीके से हो सकेगा।
- राज्य के बेरोज़गार युवक/युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2021 पारित किया गया है।
- इसके अलावा अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली की अधिसूचना के उपरांत यह अधिनियम 12 सितंबर, 2022 से संपूर्ण झारखंड राज्य में प्रभावी है।
- यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान, जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहाँ 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं, पर लागू होता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है।
- अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, द्वारा यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है, तो 40,000 रुपए वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय को नियुक्त करना होगा। इस अधिनियम का लाभ उठाने के इच्छुक झारखंड के युवाओं को रोज़गार पोर्टल पर निबंधित होना होगा।
- यदि स्थानीय कंपनियों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में सूचित किया जाता है, तो सरकार द्वारा आवश्यक कौशल के संबंध में प्रशिक्षण दिलाकर स्थानीय युवाओं को योग्य बनाने का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किया गया है।

नोट :

पलामू में पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन का गठन

चर्चा में क्यों ?

15 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत के प्राचीनतम खेलों में से एक पावरलिफ्टिंग के लिये पलामू के खेल प्रेमियों ने मिलकर राज्य के पलामू ज़िले में एक एसोसिएशन का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- एसोसिएशन का नाम पलामू डिस्ट्रिक्ट पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन रखा गया है तथा पलामू डिस्ट्रिक्ट पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष आईपीएस अधिकारी संजय रंजन सिंह को मनोनीत किया गया है, जबकि आनंद कुमार सिंह बुचुन को उपाध्यक्ष, रथीन भद्रा को महासचिव, दीपक चैटर्जी बुई को संयुक्त सचिव, राजा बागची को कोषाध्यक्ष चुना गया।
- पलामू डिस्ट्रिक्ट पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के गठन के बाद झारखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने इसे मान्यता दे दी है। अब ये संस्था स्वतंत्र रूप से अपने अधीन आने वाले खिलाड़ियों के लिये टूर्नामेंट के आयोजन से लेकर अन्य सुधारात्मक कार्य कर सकेगी।
- पलामू डिस्ट्रिक्ट पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव रथिन भद्रा ने बताया कि इस एसोसिएशन के अस्तित्व में आने से आज का युवा वर्ग, जो शारीरिक चर्चाओं को बहुत ज्यादा महत्त्व देते हैं और इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते है, उन्हें एक संगठित मंच मिलेगा
- एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय रंजन सिंह ने बताया की जल्द ही एसोसिएशन के तत्वावधान में पलामू डिस्ट्रिक्ट पावरलिफ्टिंग कंपीटीशन कराया जाएगा। इसके बाद झारखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर नेशनल जूनियर व सब जूनियर कैटेगरी का टूर्नामेंट भी कराया जाएगा।

हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट ज़ोन हॉकी चैंपियनशिप 2023

चर्चा में क्यों ?

19 मार्च, 2023 को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने झारखंड के खूँटी में आयोजित 1st हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट ज़ोन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विधिवत उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान खूँटी के उपायुक्त ने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन से प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य सफल होगा।

नोट :

- विदित है कि इस प्रतियोगिता के लिये 19 से 26 मार्च तक खूँटी के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होने वाला है।
- 1st हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट ज़ोन हॉकी चैंपियनशिप 2023 में कुल 6 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे है।
- उद्घाटन मैच झारखंड और बिहार के बीच खेला गया, जिसमें मेजबान झारखंड की महिला हॉकी टीम ने बिहार हॉकी को 11-0 से पराजित कर मैच जीत लिया। झारखंड टीम की कप्तान एडलिन बागे को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला।

राँची में उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

20 मार्च, 2023 को झारखंड के राँची के टाना भगत स्टेडियम खेलगाँव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड के इतिहास में पहली बार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर ऐसा आयोजन हुआ है।
- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है, जिसके पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों (स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) में सीबीएसई की तर्ज पर बच्चों को शिक्षा मिलनी शुरू हो चुकी है तथा आने वाले समय में 4000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वैसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा से आगे बढ़कर इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित अन्य स्ट्रीम में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार आर्थिक मदद देते हुए पढ़ाई में होने वाले सभी खर्च वहन करेगी।
- उन्होंने बताया कि देश में पहली बार इस राज्य ने अपने बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिये विदेशों में पढ़ाई करने के लिये 100% स्कॉलरशिप प्रदान किया है। राज्य सरकार के खर्च पर विदेश में पढ़ाई करने गए कुछ बच्चे डिग्रियाँ लेकर वापस राज्य पहुँचकर अच्छा कर रहे हैं, वहीं कुछ बच्चों को तो विदेशों में नौकरी भी मिल गई।
- उत्कृष्ट विद्यालय (स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) से संबंधित महत्त्वपूर्ण बातें-
- राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की भौतिक संरचना को आदर्श मानक एवं विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार निर्मित किया गया है।
- राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में आधुनिक एवं सभी आवश्यक व्यवस्थाओं सहित पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों के लिये उपयोगी पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों के साथ-साथ पत्र-पत्रिका की व्यवस्था की गई है।
- विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुझान विकसित करने तथा उनमें वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिये राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में विज्ञान लैब की अधिष्ठापना की जा रही है।
- राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में आई सीटीलैब के साथ-साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से विद्यार्थी हर दिन कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एवं साथ ही ई-कैंट के माध्यम से विषयवार विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
- राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में विभिन्न ट्रेड में व्यवसायिक शिक्षा की शुरूआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी रूचि अनुसार अपने हुनर को आगे बढ़ाना है ताकि भविष्य में वे अपने आजीविका को सहजता से आगे ले जा सकें।
- 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा 15 शिक्षकों को भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से भी प्रशिक्षित किया गया है।

नोट :

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने झारखंड को दिया 11,400 करोड़ रुपए की 21 सड़क परियोजनाओं का तोहफा

चर्चा में क्यों ?

23 मार्च, 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को 11400 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की लागत से निर्मित और बननेवाली 21 सड़क परियोजनाओं का तोहफा दिया, जिनमें 18 परियोजनाओं का शिलान्यास रांची में हुआ।

प्रमुख बिंदु

इन परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास हुआ-

- वाराणसी-राँची इकोनॉमिक कॉरिडोर के कुडू से उदयपुरा तक फोर लेन सड़क, लंबाई 39 किलोमीटर, लागत 1423 करोड़ रुपए।
- वाराणसी-राँची इकोनॉमिक कॉरिडोर के उदयपुरा से भोगू तक फोर लेन सड़क, लंबाई 50 किलीमीटर, लागत 1437 करोड़ रुपए।
- वाराणसी-राँची इकोनॉमिक कॉरिडोर के भोगू से संखा तक फोर लेन सड़क, लंबाई 49 किलोमीटर, लागत 1391 करोड़ रुपए।
- वाराणसी-राँची इकोनॉमिक कॉरिडोर के खजूरी से बिढमगंज तक फोर लेन सड़क, लंबाई 41 किलोमीटर, लागत 1232 करोड़ रुपए।
- रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के बोकारो जैना मोड़ से गोला तक फोर लेन सड़क, लंबाई 32 किमी, लागत 1127 करोड़ रुपए।
- रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के गोला-ओरमांझी तक फोर लेन सड़क, लंबाई 28 किलोमीटर, लागत 1330 करोड़ रुपए।
- लोहरदगा सड़क का बाईपास निर्माण, लंबाई 20 किमी, लागत 459 करोड़ रुपए।
- चतरा शहर का बाईपास निर्माण लंबाई 14 किलोमीटर, लागत 235 करोड़ रुपए।
- लामटा से गोनिया तक टू लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, लंबाई 18 किलोमीटर, लागत 98 करोड़ रुपए।
- दुआरी से रोल तक रोड का निर्माण, लंबाई 26 किलोमीटर, लागत 85 करोड़ रुपए।

नोट :

- डालटनगंज से राजहरा के बीच रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, लागत 84 करोड़ रुपए।
- कूटीमोड़ (चैनपुर) से हुटार तक वाया रामगढ़ ब्लॉक हेडवर्टर का निर्माण, लंबाई 24 किलोमीटर, लागत 81 करोड़ रुपए।
- बनासो से बुड़कट्टा मार्ग का निर्माण, लंबाई 28 किलोमीटर, लागत 69 करोड़ रुपए।
- मोहम्मदगंज से हैदरनगर (मोहम्मदगंज से दंगवार सड़क) वाया पनसा ओघोरी सड़क, लंबाई 17 किलोमीटर, लागत 62 करोड़ रुपए।
- चैनपुर से महुआड़ांड़ मार्ग (डुमरी तक) टू लेन सड़क का निर्माण, लंबाई 12 किलोमीटर, लागत 59 करोड़ रुपए।
- गुमला से कोलेबिरा मार्ग का निर्माण, लंबाई 47 किलोमीटर, लागत 57 करोड़ रुपए।
- गोला-चारू मार्ग पर कामता में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, लागत 35 करोड़ रुपए।
- देवलटांड़ स्थित भगवान आदित्यनाथ मंदिर एनएच-33 को जोड़नेवाले मार्ग का निर्माण, लंबाई 2 किलोमीटर, लागत 2 करोड़ रुपए।

ईस्ट ज़ोन जूनियर हॉकी प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

19 से 26 मार्च, 2023 तक हॉकी झारखंड और ज़िला प्रशासन खूंटी के संयुक्त तत्वावधान में खूंटी के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बिरसा कॉलेज कैंपस में आयोजित ईस्ट ज़ोन जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की महिला और पुरुष, दोनों टीमें चैंपियन बनी हैं।

प्रमुख बिंदु

- महिला वर्ग में हॉकी झारखंड और हॉकी मिज़ोरम के बीच हुए मैदानी खेल में दोनों ही टीम दो-दो गोल की बराबरी पर रहीं। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में झारखंड ने 2-1 से मैच जीत लिया।
- झारखंड टीम की गोलकीपर अनुपम होरो को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।
- पुरुष वर्ग का फाइनल हॉकी झारखंड और हॉकी ओडिशा के बीच खेला गया, जिसमें झारखंड ने 3-1 से जीत हासिल की।
- झारखंड टीम के दीपक सोरेंग को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।
- झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त टीमों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया।
- तीसरे एवं चौथे स्थान के लिये महिला वर्ग का मैच ओडिशा और बिहार के बीच खेला गया, जिसमें ओडिशा ने 10-0 से मैच जीतकर कांस्य पदक हासिल किया। ओडिशा की सुप्रिया कुजूर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
- पुरुष वर्ग में हॉकी बंगाल और हॉकी बिहार के बीच मैच खेला गया, जिसमें बिहार टीम 3-1 से विजयी रही। बिहार टीम के अमन कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

नोट :

झारखंड में जल्द बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 फोरलेन कॉरिडोर

चर्चा में क्यों ?

27 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों के विकास को लक्ष्य बनाकर कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य पथ निर्माण विभाग द्वारा फोरलेन वाले छह रोड कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि फोरलेन वाले ये सभी कॉरिडोर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाइवे होंगे, साथ ही इन कॉरिडोर के बनने से राज्य के अंदर यात्रा करने वालों को कम समय और कम दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को बहुत ही सहूलियत होने की संभावना है।
- जानकारी के अनुसार, इनमें 393 किमी. का ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर, 121 किमी. का इस्टर्न कॉरिडोर, 275 किमी. का नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर, 140 किमी. का सेंट्रल कॉरिडोर, 270 किमी. का टूरिस्ट कॉरिडोर और 170 किमी. का होली टूरिस्ट कॉरिडोर शामिल है।
- सभी कॉरिडोर का डीपीआर तैयार करने के लिये राज्य पथ निर्माण विभाग अनुभवी और तकनीकी रूप से दक्ष कंसल्टेंट को ज़िम्मेदारी देगा।
- जिन छह कॉरिडोर का निर्माण किया जाना तय हुआ है, जो अलग-अलग रूटों पर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएगी, वे हैं-
  - इस्ट-वेस्ट कॉरिडोर : 393 किमी. मुड़ीसेमर से चतरा-बरही-बेंगाबादमधुपुर-सारठ-पालाजोरी होते हुए दुमका तक।
  - इस्टर्न कॉरिडोर : 121 किमी. साहिबगंज से जामताड़ा-निरसा- सिंदरी-चंदनक्यारी होते हुए चांडिल तक।
  - नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर : 275 किमी. झुमरीतिलैया से एनएच-2 पर (अंतकीडीह)- विष्णुगढ़ पेटरवारकसमार-बरलंगा-सिल्ली-रड़गांवसरायकेला-चाईबासा-जैतगढ़ होते हुए ओड़िशा की सीमा तक।
  - सेंट्रल कॉरिडोर : 140 किमी. रांची से बुढ़मू-टंडवा-चतरा-हंटरगंज होते हुए डोभी बिहार की सीमा तक।
  - टूरिस्ट कॉरिडोर : 270 किमी. मिलन चौक (सिल्ली रंगामाटी रोड) से सारजमडीह-तमाड़-खूंटी गोविंदपुरसिसई-घाघरा-नेतरहाट-गारू-सरयू-लातेहार-हेरहंज-बालूमाथमैक्लुस्कीगंज होते हुए चामा मोड़ तक।
  - होली टूरिस्ट कॉरिडोर : 170 किमी. रांची से ओरमांझी-गोला-रजरप्पा- डुमरी और गिरिडीह होते हुए देवघर तक। यह लुगुबुरू, पारसनाथ और बाबाधाम को आपस में जोड़ेगा।

नोट :

झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में 44 फैसलों को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

27 मार्च, 2023 झारखंड कैबिनेट की बैठक में 44 फैसलों को मंजूरी दी गईं, जिसमें रांची में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के अलावा सिमडेगा-खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आधारभूत संरचना का विकास सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट की बैठक में राज्य के शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को दिये जा रहे सातवें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय वेतन में सरकार के वित्तीय भार निर्धारण की स्वीकृति भी दी गई।
- मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं -
  - राजधानी राँची में EPC Model पर ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज-2 के लिये कुल 57,82,58,156/- रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  - वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये Network Infrastructure Development के तहत पायलट परियोजना के रूप में सिमडेगा खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा दुमका ज़िला के दुमका प्रखंड के Saturation के लिये कुल 84 करोड़ रुपए खर्च की स्वीकृति दी गई।
  - झारखंड राज्यांतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई।
  - झारखंड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम, विद्यालयों/पीवीटीजी, आवासीय प्राथमिक विद्यालयों/अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों/अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि, विस्तार एवं संचालन हेतु इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई।
  - एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना, टंडवा क्षेत्र में पड़ने वाली गहरी जलाशय हेतु अर्जित भूमि में से आंशिक रकबा 25.99 एकड़ भूमि ASH DYKE एवं WATER RESERVOIR निर्माण हेतु एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना (NKSTPP), टंडवा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
  - 'झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में पर्यटनकला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को आवंटित कार्य-दायित्व राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कोर', को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्य दायित्व में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  - 'नमामि गंगे योजना'के अंतर्गत 310.11 करोड़ रुपए की लागत पर Interception & Diversion (I&D) and Sewerage Treatment Plant (STP) परियोजना, रामगढ़ को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  - केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के अंतर्गत 4648.58 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बड़कीसरैया शहरी जलापूर्ति परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  - झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  - झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करते हुये झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 को गठन की स्वीकृति दी गई।

नोट :

झारखंड के खिलाड़ियों को विश्व चैंपियनशिप में भागीदारी करने पर भी मिलेगा अब कैश अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

28 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के खिलाड़ियों को अब विश्व चैंपियनशिप या विश्व कप में भागीदारी पर भी कैश अवॉर्ड दिया जाएगा। इसके लिये राज्य के खेल निदेशालय की ओर से खिलाड़ियों को कैश अवॉर्ड देने से संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस बार कुछ प्रतिस्पर्धा में भागीदारी के लिये भी कैश अवॉर्ड दिये जा रहे हैं। पहले के कैश अवॉर्ड की नियमावली को बदल दिया गया है, जिसके बाद खिलाड़ियों को मिलने वाले कैश अवॉर्ड में भी बढ़ोतरी हो गई है।
- विदित है कि एक से दो वर्ष के अंतराल में होने वाले इस आयोजन में पहले भागीदारी के लिये कैश अवॉर्ड नहीं मिलता था, लेकिन अब खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये सीनियर और जूनियर, दोनों स्तर पर दिया जाएगा।
- राज्य के खिलाड़ियों को कुल 24 प्रतिस्पर्धाओं के लिये कैश अवॉर्ड दिया जाएगा। केवल एक स्पर्धा के लिये कैश अवॉर्ड नहीं मिलेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कम-से-कम आठ देशों की सहभागिता हो, उसमें कोई भी पदक जीतने पर खिलाड़ियों को किसी भी तरह का कोई कैश अवार्ड नहीं दिया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ओलंपिक में भी भागीदारी पर दिव्यांग खिलाड़ियों को 50 हज़ार रुपए का कैश अवॉर्ड दिया जाएगा।

नाबार्ड ने झारखंड के लिये बनाई 43 हज़ार करोड़ की क्रेडिट योजना

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को राँची में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने झारखंड मंत्रालय सभागार में स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिये 43,725 करोड़ रुपए की राज्य क्रेडिट योजना प्रस्तुत की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह क्रेडिट योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के 34,458 करोड़ रुपए से करीब 9,267 करोड़ रुपए ज्यादा है।
- कार्यक्रम का थीम 'राज्य बजट का क्रेडिट प्लान के साथ प्रसार' रखा गया था।
- इस अवसर पर नाबार्ड के सीजीएम एमएस राव ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार के महत्त्व और उद्देश्य पर प्रकाश डाला तथा किसानों के लाभ के लिये राज्य में अधिक किसान उत्पादक संगठनों के गठन तथा उनके द्वारा हाई-टेक कृषि अपनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने नाबार्ड की ओर से स्टेट फोकस पेपर प्रस्तुत किया।
- स्टेट फोकस पेपर में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के सभी 24 ज़िलों में राज्य के 4000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण के मुकाबले बैंकों द्वारा 15,000 करोड़ कर्ज दिया सकता है। राज्य के किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिये कई योजनाओं में वित्तीय मदद में इज़ाफा किया गया है। इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने से बेरोज़गारी, गरीबी और पलायन की स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
- इस बार केंद्र सरकार की तरह ही नाबार्ड का फोकस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर दिखा। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा 51% ऋण संभावना देखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में 22071.87 करोड़ रुपए का ऋण प्रस्ताव रखा गया है।

नोट :